Vol 4 Issue 4 May 2014

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest,Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Indian Streams Research Journal
ISSN 2230-7850
Volume-4 | Issue-4 | May-2014
Available online at www.isrj.net

जयप्रकाश नारायण के 'सम्पूर्ण क्रान्ति' आन्दोलन में मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन

सुमीत द्विवेदी

शोध छात्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ.प्र.

सारांश :- स्वतन्त्र भारत का सपना केवल कुछ लोगों के हित साधन का ही सपना बनकर रह गया था, बाकी जनता की स्थिति में कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा था। गरीबी और अमीरी का अन्तर बढ़ने लगा था। इंदिरा गांधी के 'गरीबी मिटाओ' के आह्वान के साथ सत्ता में आने पर भी इसमें कोई सुधार आता न दिखा, उल्टे अधिक विकृतियां दिखाई देने लगीं। कृषि में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पा रही थी, औद्योगीकरण के बावजूद मंदी का दौर जारी था, बेरोजगारी, महंगाई नई ऊंचाईयां छू रही थीं। देश में निराशा का माहौल व्याप्त हो रहा था। गुजरात और बिहार में छात्र विद्रोह पर उतर आए थे। ऐसे में विख्यात् गांधीवादी चिंतक और समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश में व्याप्त असंतोष और भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दिया और इसे नाम दिया ''सम्पूर्ण क्रान्ति का। सम्पूर्ण क्रान्ति के तेजी से देश में (विशेषकर उत्तर भारत में) फैलाव और खुद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के चुनाव लड़ने से 6 साल तक प्रतिबंध के प्रतिकूल निर्णय के प्रतिउत्तर में इन्दिरा गांधी ने देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल के नाम पर देश के नागरिकों पर अनेक प्रतिबन्धों को थोपा जाने लगा, मीडिया को परतन्त्र बनाने और पीत पत्रकारिता करने को मजबूर किया गया, उसे आचार संहिताओं में बांधकर प्रतिबंधित किया गया। प्रस्तुत शोधपत्र जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन की स्थितियों तथा इस आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में मीडिया की भूमिका का मूल्यांकन करता है।

मुख्य शब्द –आन्दोलन, जनान्दोलन, जयप्रकाश नारायण, सम्पूर्ण क्रान्ति, बिहार आन्दोलन, गुजरात आन्दोलन, इन्दिरा गांधी, आपातकाल, पत्रकारिता, मीडिया, सेंसरशिप, लोकतन्त्र, समाचार पत्र–पत्रिकाएं।

प्रस्तावना :

1. जयप्रकाश नारायण का सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन –

1.1 आन्दोलन की पृष्ठभूमि –

बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखने पर स्पष्ट लगता है कि आजाद भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1974–75 के बिहार आन्दोलन के रूप में घटी, जो बाद में सम्पूर्ण क्रान्ति में परिवर्तित हुई। लेकिन इस जनान्दोलन के पीछे के कारण जितने तात्कालिक रहे उससे भी ज्यादा लम्बे समय से देश में पनप रहे जनाक्रोश से उपजे थे। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता कम होती जा रही थी। भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। इंदिरा गांधी पर गहन शोध करने वाली कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं– ''भ्रष्टाचार फल–फूल रहा था। बेशक ये कोई नई बात नहीं थी, नेहरू और शास्त्री के शासन में भी इसके आरोप लगते रहे थे लेकिन इंदिरा गांधी के शासन में तो सरकार के प्रत्येक कामकाज में भ्रष्टाचार ने महामारी का रूप ले लिया है।''[1]

दूसरी ओर मंदी, बढ़ती बेरोजगारी, आकाश छूती महंगाई और खाद्य पदार्थों की कमी आदि ने मिल–जुलकर एक गंभीर संकट उपस्थित कर दिया था। 1971 के दौरान बांग्लादेश से आए एक करोड़ शरणार्थियों के बोझ ने अन्न भंडार खाली कर दिया, साथ ही बांग्लादेश युद्ध के खर्चे ने मिलकर विशाल बजट घाटा उपस्थित किया। विदेशी मुद्रा भण्डार खाली हो गया था। 1972–73 के वर्षों में देश के अधिकतर हिस्सों में भयंकर सूखा पड़ा और खाद्यान्नों की भीषण कमी हो गई, इसके परिणामस्वरूप उनकी कीमतों में आग लग गई।[2] ग्रामीण या शहरी गरीबी एवं आर्थिक विषमताओं के मोर्चे पर शायद ही कुछ किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गीय तथा जातीय शोषण में कोई कमी नहीं आयी थी। असंतोष उभरने का तात्कालिक कारण आर्थिक परिस्थितियों में स्पष्ट गिरावट थी। सूखे के कारण विद्युत उत्पादन भी घटने लगा और औद्योगिक वस्तुओं की मांग कम हो गई। नतीजा हुआ– औद्योगिक मंदी तथा बेरोजगारी में वृद्धि। 1973 में कुख्यात् तेल संकट भी पैदा हुआ। विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत चार गुना बढ़ गई। परिणामस्वरूप खाद एवं पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में भारी बढ़ोत्तरी हुई। इससे दूसरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती चली गईं और साल भर में ही कीमतों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देश के कई हिस्सों में अनाज

के लिए दंगे होने लगे।[3] 1972–73 में ही देश के विभिन्न भागों में हड़तालों की लहर चलने लगी। केवल मुम्बई में लगभग 12000 हड़तालें हुईं। इसकी चरम परिणति मई 1974 की अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल के रूप में हुई। यह हड़ताल 22 दिनों तक चलती रही और आखिर में तोड़ दी गई। मजदूरों के बीच श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और भी कम हो गई।

कानून तथा व्यवस्था की हालत लगातार खासकर 1974–75 के दौरान और भी खराब हो गई। हड़तालें, छात्र–प्रदर्शन तथा जुलूस अक्सर हिंसक हो उठते थे। कई कॉलेज तथा विश्वविद्यालय लम्बे समय के लिए बंद कर दिये गए। मई 1973 में उत्तर प्रदेश में पीएसी(पुलिस) ने बगावत कर दी और छात्रों के आन्दोलन को कुचलने से मना कर दिया। जब सेना को भेजा गया तो उनके साथ हुई मुठभेड़ में पैंतीस सिपाही और सैनिक मारे गए। आर्थिक, राजनीतिक तथा कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति से निबटने के लिए दृढ़ और स्पष्ट नेतृत्व की आवश्यकता थी, परन्तु ऐसा होता दिख नहीं रहा था। तीन महत्वपूर्ण सामाजिक तबकों का कांग्रेस से अलगाव बढ़ना एक महत्वपूर्ण तथा नई परिघटना थी। जहां गरीब अभी भी अनमने ढंग से ही सही इसका समर्थन कर रहे थे, वहीं मध्यवर्ग बढ़ती महंगाई तथा भ्रष्टाचार के कारण, धनी किसान भूमि सुधार की धमकी के कारण तथा पूंजीपति समाजवाद की चर्चा, बैंक और कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण तथा इजारेदार विरोधी कदमों के कारण कांग्रेस और इंदिरा गांधी से दूर हट रहे थे।[4]

1.2 क्रान्ति का आह्वान –

''जब मैं देश के नाजुक स्वास्थ्य की दशा की समीक्षा करता हूं तो यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि यह सब गिरते नैतिक मूल्यों का नतीजा है। सार्वजनिक जीवन का कोई भी क्षेत्र, चाहे वह राजनीति हो या सरकार या शिक्षा या कारोबार, व्यापारिक संगठन या सामाजिक संगठन – ऐसा नहीं है जो गिरते नैतिक मूल्यों से अछूता हो।''[5] जयप्रकाश नारायण का यह कथन तत्कालीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में उनके विचारों का स्पष्ट संकेत था। रैडिकल ह्यूमनिष्ट के अगस्त 1972 के अंक में कांग्रेस के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी अधिक स्पष्टता दिखने लगी थी। वे लिखते हैं– ''1971 और 1972 की भारी चुनावी जीतों के बावजूद कांग्रेस आज खोखले ढांचे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।''[6] इसी समय विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संकटों को दो जन आन्दोलनों ने एक राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया। गुजरात तथा बिहार में गुटबंदी की शिकार कांग्रेस सरकारों के खिलाफ ये आन्दोलन चले।

गुजरात आन्दोलन स्वयं शुरू हुआ। मेस–दर में बढ़ोत्तरी के खिलाफ अहमदाबाद और मोरवी के छात्र विद्रोह पर उतर आए और यह आन्दोलन अनाज, तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों मे तीव्र वृद्धि, जमाखोरी तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जन–जन तक पहुंच गया। गुजरात आन्दोलन में जयप्रकाश की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, लेकिन इस आन्दोलन ने बिहार आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी।[7]

बिहार आन्दोलन की शुरूआत जे.पी. ने नहीं की थी। यह आन्दोलन भी छात्र आन्दोलन के रूप मे शुरू हुआ। लेकिन जल्द ही इसके साथ बिहार का जनमानस खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। वर्षों के भ्रष्टाचार और कुशासन ने राजनीतिज्ञों, पुलिस तथा प्रशासनिक तन्त्र के खिलाफ एक अप्रकट क्रोध भर दिया था। ऐसे में छात्रों ने आन्दोलन के दायरे को विस्तृत करने हेतु जयप्रकाश नारायण से आन्दोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। जयप्रकाश नारायण, जो जे.पी. के रूप में लोकप्रिय थे, ने अपने राजनीतिक सन्यास को त्यागकर इस आन्दोलन का नेतृत्व करने का निर्णय किया। उन्होंने ''सम्पूर्ण क्रान्ति'' का नारा दिया जो 'उस पूरी व्यवस्था के विरूद्ध संघर्ष था जिसने हर व्यक्ति को भ्रष्ट बनने के लिए मजबूर कर दिया था।8 कांग्रेस सरकार के त्यागपत्र और विधानसभा भंग करने की मांग करते हुए उन्होंने छात्रों और जनता से कहा कि वे मौजूदा विधायकों पर त्यागपत्र के लिए दबाव डालें, सरकार को ठप कर दें, सरकारी कार्यालयों और विधानसभा को घेराव करें, पूरे राज्य में समानान्तर जन सरकार गठित करें और कर देना बन्द कर दें।

जयप्रकाश नारायण ने भी बिहार से निकलकर सम्पूर्ण देश के स्तर पर फैले हुए भ्रष्टाचार और कांग्रेस एवं इंदिरा गांधी के निष्कासन को लेकर आन्दोलन संगठित करने का निर्णय लिया। इंदिरा गांधी को लोकतन्त्र के दुश्मन और भ्रष्टाचार के स्रोत के रूप में अब देखा जाने लगा था। जे.पी. अब नियमित रूप से पूरे देश का दौरा करने लगे और दिल्ली एवं उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में जहां जनसंघ या समाजवादियों के गढ़ थे, वहां भारी भीड़ इकट्ठी करने लगे। जे.पी. आन्दोलन ने खासतौर पर छात्रों, मध्यवर्ग, व्यापारियों तथा बुद्धिजीवियों के एक हिस्से का व्यापक समर्थन हासिल किया। इसे सभी गैर–वामपंथी पार्टियों का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। जे.पी. आन्दोलन के गैर–संसदीय रूझानों की भर्त्सना करते हुए इंदिरा गांधी ने जे.पी. को बिहार एवं सम्पूर्ण देश में अपनी लोकप्रियता की परीक्षा आगामी चुनावों में कर लेने की चुनौती दी जो फरवरी–मार्च 1976 में होने वाले थे। जे.पी. ने चुनौती स्वीकार की और उन्हें समर्थन देने वाली पार्टियों ने इस उद्देश्य से राष्टीय सहयोग समिति के गठन का फैसला लिया। इस समय ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे पर फैसला लोकतांत्रिक चुनावी तरीके से हो जाएगा कि कौन दरअसल भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिन्हा द्वारा दिए गए एक फैसले ने भारतीय राजनीति को अचानक ही एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया। राजनारायण द्वारा दायर की गई याचिका पर फैसला देते हुए अदालत ने श्रीमती इंदिरा गांधी को भ्रष्ट चुनाव आचरण में लिप्त होने का दोषी पाया और उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। इस फैसले में यह भी निहित था कि अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए वे अयोग्य घोषित की जा चुकी थीं, साथ ही किसी पद पर आसीन भी नहीं हो सकती थीं।[9] इसलिए उनका प्रधानमंत्री बने रहना संभव नहीं रह गया था।

इंदिरा गांधी ने त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। इस बीच श्रीमती इंदिरा गांधी को एक और राजनीतिक धक्का लगा। 13 जून 1975 को गुजरात विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। 182 सदस्यों के सदन में विपक्षी जनता मार्चे को 87 स्थान प्राप्त हुए जबकि कांग्रेस को मात्र 75 स्थान मिले। आश्चर्यजनक यह कि जनता मोर्चे ने उसी चिमनभाई पटेल के साथ गठबंधन सरकार बनाने में सफलता पायी, जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार और कुशासन को लेकर यह जनान्दोलन शुरू किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले और गुजरात विधानसभा के नतीजों ने विपक्षी आन्दोलनों को फिर से जगा दिया। लेकिन जे.पी. और विपक्षी पार्टियों का गठबंधन, श्रीमती इंदिरा गांधी की सर्वोच्च न्यायालय में अपील पर फैसले और अगले आठ महीनों में होने वाले आम चुनावों के नतीजे के लिए

इंतजार करने को तैयार नहीं था। उन्होंने इस अवसर का पूरा फायदा उठाने का निश्चय किया और श्रीमती गांधी पर 'भ्रष्ट तरीकों से हथियाए गए पद से चिपके रहने' का आरोप लगाते हुए उनसे त्यागपत्र की मांग की। इस मुद्दे पर दबाव डालने के लिए उन्होंने राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का आह्वान किया। 25 जून को दिल्ली में हुई एक रैली में उन्होंने यह घोषणा की कि इंदिरा गांधी को त्यागपत्र देने के लिए दबाव डालने के लिए 29 जून से एक सप्ताह का राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आन्दोलन और जुलूस आदि का आयोजन किया जाएगा। इस आन्दोलन का अन्त सैकड़ों हजारों आन्दोलनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री निवास के घेराव में होना था।[10] अपनी रैली में दिए गए भाषण में जे.पी. ने जनता से आग्रह किया कि वे सरकार के कामकाज का चलना असंभव बना दें तथा एक बार फिर शसस्त्र सेनाओं, पुलिस बल तथा सरकारी अधिकारियों से अपील की कि वे किसी भी सरकारी आदेश को न मानें और उन आदेशों को ''गैर कानूनी तथा गैर संवैधानिक'' मानें।

1.3 आंतरिक आपातकाल –

श्रीमती इंदिरा गांधी की तात्कालिक प्रतिक्रिया 26 जून को देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा के रूप में सामने आयी। गांधी शांति प्रतिष्ठान के सचिव राधाकृष्ण द्वारा 26 जून 1975 की सुबह तीन बजे वहां ठहरे जयप्रकाश नारायण को जगाया गया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई थी, बताया गया कि देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है। इंदिरा गांधी ने सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाओं को निलंबित करते हुए संविधान की धारा 352 के तहत आंतरिक आपातकाल लागू किए जाने की घोषणा की। परन्तु उन्होंने यह वादा किया कि जैसे ही परिस्थितियां मौका देंगी, वैसे ही सामान्य हालात बहाल कर दिए जाएंगे। इस घोषणा ने संविधान के संघीय प्रावधानों को बर्खास्त कर दिया। सरकार ने प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लागू कर दी और सरकार के सभी विरोधों पर पाबंदी लगा दी। 26 जून को तड़के ही विपक्ष के सैकड़ों प्रमुख नेताओं को आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन कानून (मीसा) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और चन्द्रशेखर जैसे कांग्रेसी विक्षुब्ध शामिल थे। कई शिक्षाशास्त्री, पत्रकार, ट्रेड यूनियन नेता तथा छात्र नेता भी जेल की सीखचों के अन्दर बंद कर दिए गए।[11] गिरफ्तार किए गए लोगों को धीरे–धीरे छोड़ दिया गया। अनेक सांप्रदायिक एवं उग्र–अतिवामपंथी संगठनों जैसे– आरएसएस, आनन्द मार्ग, जामात–ए–इस्लामी तथा माओवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (एमएल) पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पूरे आपातकाल के दौरान गिरफ्तारियां चलती रहीं, हालांकि ज्यादातर गिरफ्तार लोगों को कुछ दिनों या महीनों बाद छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर इन उन्नीस महीनों में एक लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में समाज विरोधी लोग जैसे– तस्कर, जमाखोर, कालाबाजारी करने वाले एवं जाने माने गुंडे भी बड़ी संख्या में शामिल थे।

संसद बिल्कुल ही अप्रभावी बना दी गई थी। विपक्ष के कुछ बहादुर सांसदों को, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनके भाषणों को बेअसर बना दिया गया था क्योंकि उन्हें अखबारों में रिपोर्ट करने की इजाजत ही नहीं थी। राज्य सरकारों पर भी कड़ा नियंत्रण लगा दिया गया था। तमिलनाडु में डीएमके तथा गुजरात में जनता पार्टी की दोनों ही गैर कांग्रेसी सरकारों को जनवरी और मार्च 1976 में उनके पूरी तरह आज्ञाकारी होने के बाद बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को पूरी तरह विश्वस्त नहीं होने के कारण बदल दिया गया। कांग्रेस पार्टी पर भी कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। पार्टी के अन्दर आंतरिक जनवाद को भी कमोवेश पूरी तरह कुचल दिया गया। 1976 के अंतिम हिस्से में संजय गांधी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस अपने मातृ संगठन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी। विज्ञप्तियों, कानूनों और संविधान संशोधनों की एक श्रंखला द्वारा कार्यपालिका के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया गया।

नागरिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हुए जुलाई 1975 में भारत सुरक्षा कानून और मीसा में भी संशोधन किया गया। नवंबर 1976 में संविधान के आधारभूत नागरिक अधिकारवादी ढांचे को 42वें संशोधन द्वारा बदलने की कोशिश की गई। संविधान संशोधनों में न्यायपालिका द्वारा पुर्नमूल्यांकन करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यह कहा गया कि न्यायपालिका गरीबों के लिए किए जाने वाले उपायों जैसे– 'भूमि सुधार कानून' आदि का मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर विरोध करती है। यह तय कर लिया गया कि संविधान संशोधन करने के संसद के अधिकार पर कोई सीमा तय नहीं की जा सकती है। मौलिक अधिकारों को अप्रत्यक्ष रूप से दुर्बल बनाने के लिए उसे संविधान में सन्निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों का मातहत बना दिया गया।[12]

अतः आपातकाल ने प्रधानमंत्री के हाथों में असीम राजकीय तथा पार्टी शक्ति संकेन्द्रित कर दी जिनका इस्तेमाल श्रीमती इंदिरा गांधी अपने इर्द–गिर्द जुटे राजनीतिज्ञों और अधिकारियों की मदद से कर सकती थी। हांलांकि सार्वजनिक व्यवस्था और अनुशासन फिर से कायम हो जाने के साथ अनेक लोगों ने राहत महसूस की, उन्हें लगा देश को अव्यवस्था और अराजकता से बचा लिया गया है। पत्रकार इन्दर मल्होत्रा लिखते हैं– ''लगातार हड़तालों, विरोध प्रदर्शनों, धरना और पुलिस से झड़पों के बाद सामान्य और व्यवस्थित जीवन की वापसी का ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया। कम से कम अपने आरंभिक महीनों में आपातकाल ने भारत में एक ऐसी शांति स्थापित की जो कई वर्षों से नहीं देखी गई थी।[13] सबसे अधिक स्वागत योग्य कदम था– कीमतों की स्थिति में नाटकीय सुधार। खाद्य पदार्थों साहित सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में कमी आई और दुकानों में उनकी उपलब्धता बढ़ गई।

आपातकाल को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए 1 जुलाई को बहुद्देशीय 20 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा इंदिरा गांधी द्वारा की गई। इस कार्यक्रम को लागू करने की गंभीर कोशिश भी की गई और कीमतों में कमी, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि तथा जमाखोरी, तस्करी एवं कर की चोरी रोकने के प्रयासों के कुछ शीघ्र परिणाम भी प्राप्त हुए। परन्तु 20 सूत्री कार्यक्रम की अन्तरात्मा ग्रामीण गरीबों के उत्थान से सम्बन्धित इसका एजेंडा थी। समूचे तौर देखा जाए तो इस कार्यक्रम का ग्रामीण इलाकों से जुड़ा हिस्सा बड़े भू–स्वामियों और धनी किसानों एवं असहानुभूतिपूर्ण अफसरशाही द्वारा खड़े किए गए अवरोधों के कारण ठंडा पड़ता चला गया। परिणामस्वरूप यद्यपि इस कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबों को कुछ राहत जरूर दी परन्तु यह उनकी मौलिक परिस्थिति में बहुत ही कम सुधार ला पाया। आपातकाल की अलोकप्रियता में वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण संविधान से परे एक शक्ति केन्द्र का विकास था। श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के इर्द–गिर्द इस शक्ति केन्द्र का विकास हुआ था जो कांग्रेस या सरकार में किसी भी पद पर आसीन नहीं थे। अप्रैल 1976 तक संजय गांधी एक समानान्तर

सत्ता के रूप में उभर चुके थे और सरकार एवं प्रशासन के क्रियाकलापों में अपनी मर्जी के अनुसार हस्तक्षेप करते थे। जुलाई 1976 में संजय ने अपना चार सूत्री कार्यक्रम रखा, जो शीघ्र ही अधिकारिक बीस सूत्री कार्यक्रम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। ये चार सूत्र थे : विवाह के समय दहेज न लें, परिवार नियोजन अपनाएं और परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखें, वृक्ष लगाएं और साक्षरता बढ़ाएं। संजय गांधी झुग्गी झोपड़ियों तथा सड़कों, बाजारों, पार्कों एवं ऐतिहासिक भवनों पर अवैध रूप से बने मकानों और अन्य ढाचों को हटाकर शहरों का सौंदर्यीकरण करने के लिए भी कटिबद्ध थे।[14]

संजय गांधी के दबाव में आकर सरकार ने परिवार नियोजन को मजबूती से बढ़ावा देने का फैसला किया जो कई बार बहुत ही मनमाने, अवैध तथा निरंकुश तरीके से किया गया। समझाने बुझाने और प्रलोभन देने की जगह जोर–जबर्दस्ती और दबाव को धीरे–धीरे अधिक महत्व दिया जाने लगा। बाद में तो अनिवार्य नसबंदी लागू किया जाने लगा। झुग्गी–झोपड़ियां उजाड़ने और अवैध ढांचों को गिराने का काम भी परिवार नियोजन की तरह ही चलाया जा रहा था परन्तु उसमें और भी ज्यादा क्रूरता और लापरवाही बरती गई थी। इस प्रकार दमन और भय, भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरूपयोग के पहले से चले आ रहे माहौल को संजय गांधी के निर्देशन में चलाए जा रहे अत्याचारों ने और भी बदतर बना दिया। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने अचानक आपातकाल समाप्ति की घोषणा की, 16 मार्च 1977 को स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव हुए। चुनाव परिणामों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ।

2. मीडिया की भूमिका –

मीडिया जब अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ अन्तःक्रिया करता है तब मीडिया–संदेशों की उत्पत्ति या उपलब्धि होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मीडिया और सामाजिक संरचना के अन्य तत्व अनेक स्तरों पर अलग–अलग ढंग से एक–दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह संश्लिष्ट प्रक्रिया सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों की सापेक्षिता में सम्पन्न होती है। इसका अर्थ यह है कि सरकारी एजेंसियों, राजनीतिक दलों, व्यावसायिक कम्पनियों, सामाजिक समूहों और सामाजिक आन्दोलनों आदि के कार्यों और मीडिया के कार्यों में पारस्परिक निर्भरता होती है। मीडिया के संदेश अन्य संस्थाएं अपने वातावरण के सन्दर्भ में ग्रहण करती हैं और उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं। इसलिए जिस वातावरण में मीडिया का उपयोग और प्रभाव घटित होते हैं उसका विश्लेषण सामाजिक परिवर्तन की दिशा और गति को समझने के लिए आवश्यक है, साथ ही परिवर्तन को बढ़ावा देने या रोकने में मीडिया की भूमिका को समझने के लिए भी आवश्यक है।[15]

वास्तव में मीडिया अपनी अन्तर्निहित अभिप्रेरणा के अनुसार ही विषयवस्तु का चयन और सम्प्रेषण करता है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि मीडिया तटस्थ और निरपेक्ष नहीं होता है। मीडिया में यथार्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा विशेष रूप से चुना हुआ और बनाया हुआ होता है। अतः मीडिया समाज के साथ अपने सम्बन्धों में पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं है। वह किसी न किसी रूप में उन संस्थाओं, व्यक्तियों और प्रक्रियाओं के प्रभाव और नियंत्रण में कार्य करता है जो जनमत को मोड़ने और बदलने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करने में समर्थ होते हैं। संचार माध्यमों का विकास समाज में अभिव्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। अर्थव्यवस्था और शासन तन्त्र के रूपों में परिवर्तन से संचार माध्यमों के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है।[16] संचार माध्यमों की इस प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में ही जे.पी. की सम्पूर्ण क्रान्ति तथा आपातकाल के दौर में मीडिया की स्थिति को देखा जाना चाहिए। चूंकि यह आन्दोलन मुख्य रूप से उत्तर भारत के हिन्दी भाषी क्षेत्रों में फैला व प्रभावी हुआ इसलिए उस वक्त के हिन्दी के समाचार पत्र–पत्रिकाओं की तत्कालीन स्थिति व कार्यशैली का विवेचन अनिवार्य है।

स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद शुरू हुए समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' ने अपनी निर्भीक पत्रकारिता की वजह से देश की जनता में अपनी जगह बना ली थी। सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन और आपातकाल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह समाचार पत्र अपने पत्रकारीय मानडण्डों पर खरा उतरता है। पहले इसने गुजरात और बिहार क्रान्ति से सम्बन्धित खबरों को महत्व की जगहें दीं और फिर देश में बन रहे निराशा के माहौल तथा जयप्रकाश नारायण द्वारा सम्पूर्ण क्रान्ति का नेतृत्व करने से सम्बन्धित खबरों को जमकर छापा। हालांकि आपातकाल के दौर में अन्य समाचार पत्रों की तरह दैनिक जागरण पर भी प्रतिबन्ध लागू थे, लेकिन इसने सरकारी प्रतिबन्धों पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। 27 जून 1975 के अंक में संपादकीय स्थान रिक्त छोड़ दिया गया। ऊपर लिखा– ''नया लोकतन्त्र ?'' ''(सेंसर लागू)'' और नीचे लिखा– ''(कृपया शान्त रहें)''''(देखें अगला पेज)''।[17] जब बहुत से समाचार पत्र (अंग्रजी के लगभग सभी) आपातकाल के गुणगान में लगे हुए थे, तब जागरण ने निर्भीक अभिव्यक्ति और सत्य की प्रतिष्ठा का परिचय दिया। वहीं 'आज' समाचार पत्र जिसने आजादी की लड़ाई में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया, जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन का भरपूर समर्थन किया था और जो अपने कर्तव्य में लिखता भी है कि ''हमारा कर्तव्य बुरे की बुराई को प्रकट करना है। हमारा कर्तव्य सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा करना है और हमारा कर्तव्य सार्वजनिक जीवन को पवित्र कर देश में एकता और प्रीति को बढ़ाना है।''[18] उसने आपातकाल के दिनों में आपातकाल का विरोध किया, लेकिन समाचारों तथा लेखों पर सरकारी सेंसरशिप के चलते वे लेख जनता तक नहीं पहुंचे, सरकारी पाबंदी से सम्पादकों के हाथों भी बंधे थे।[19]

अपने पहले अंक से ही कांग्रेस समर्थक पत्र का दर्जा प्राप्त 'हिन्दुस्तान' समाचार पत्र ने आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा प्रेस पर सेंसरशिप लाद देने के निर्णय के बावजूद अपनी समस्त पत्रकारीय मर्यादाओं को ताक पर रखकर आपातकाल और इंदिरा गांधी के समर्थन की खबरें छापीं। आपातकाल के विरोध में चल रही गतिविधियों तथा जे.पी. आन्दोलन की खबरों को इस पत्र ने यथासम्भव दबाने का काम किया। वैसे तो आपातकाल को लेकर प्रायः सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में स्पष्ट समर्पण भाव दिखाई देता है, पर हिन्दुस्तान के तत्कालीन पृष्ठों पर समर्पण के साथ आपातकाल के समर्थन की स्थिति दिखाई देती है। आपातकाल की घोषणा के बाद हिन्दुस्तान के 28 जून 1975 के अंक का मुख्य शीर्षक इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया वक्तव्य था– ''जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन को देश के बाहर से प्रोत्साहन''। इसके नीचे उपशीर्षक था– 'भीतर नक्सलियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व मार्क्सवादियों का समर्थन'। इसी दिन एक दूसरा शीर्षक था– ''सारे देश में स्थिति सामान्य रही'', जबकि स्थिति इसके उलट थी। इसके अलावा पूरे समय तक हिन्दुस्तान अखबार लगातार अपनी संपादकीय के माध्यम से आपातकाल की वकालत करता रहा।[20]

आपातकाल के समय पत्र–पत्रिकाओं की रीति–नीति स्पष्ट करते हुए पत्रकार प्रमोद जोशी कहते हैं– ''इमरजेन्सी के दौरान एक

बात जो समझ में आई वह यह थी कि इस दौरान सबसे पहले दिल्ली के राष्ट्रीय अखबारों ने घुटने टेके। जो क्षेत्रीय अखबार थे, उन्होंने प्रतिरोध किया या कहें इमरजेन्सी की हां में हां मिलाने में विलम्ब किया। यह तो स्पष्ट था कि सभी अखबारों की दिक्कत थी कि उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भारत सरकार के निर्देशों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, वरना वे अखबार बन्द हो जाते। ऐसे में स्थिति और खराब होती। अनेक अखबार बन्द भी हुए, लेकिन इमरजेन्सी के बाद जब वे फिर से खुले तो उन्होंने आपातकालीन ज्यादतियों के बारे में खूब छापा''।[21] दैनिक 'नवभारत' का भी आरम्भ से काग्रेस की तरफ झुकाव था। पत्र ने न काहू से दोस्ती न काहू से बैर की नीति का अनुसरण करते हुए पहले जे.पी. आन्दोलन के दौरान सामान्य रूप से आन्दोलन की खबरें प्रसारित कीं, लेकिन सरकार के पक्ष को भी सामने रखा। वहीं आपातकाल के दौरान उसने शासन से बैर मोल नहीं लिया। पत्र के पूर्व सम्पादक श्री गोविन्दलाला वोरा कहते हैं– '' आपातकाल के समय सभी समाचार पत्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। नवभारत पर भी नियंत्रण का प्रयास था। समाचार प्रकाशन से पूर्व नियुक्त शासकीय अधिकारी को समाचार दिखाया जाना अनिवार्य था, लेकिन नवभारत के समाचारों को कभी नहीं देखा गया, उन्हें विश्वास था कि नवभारत में सरकार विरोधी समाचार नहीं प्रकाशित होंगे।[22]

जहां तक 'धर्मयुग' जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका का सवाल है। पत्रिका के तत्कालीन संपादक डॉ. धर्मवीर भारती ने बिहार आन्दोलन की पृष्ठभूमि और उसके निरन्तर बढ़ते स्वरूप को लेखों व चित्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। धर्मयुग ने गुजरात तथा बिहार आन्दोलनों को लेख, फीचर, रिपोर्ताज, परिचर्चा, सर्वेक्षणों के जरिए भरपूर वैचारिक समर्थन दिया और जनमानस तैयार किया।[23] धर्मयुग लिखता है– ''आज जब प्रायः सभी दल और राजनीतिज्ञ इस या उसके भ्रष्टाचार अथवा नीतिविहीन अवसरवादिता में उलझे हुए हैं, तब लोकशाही से सामान्य जन का विश्वास पूरी तरह उठ जाए, उससे पहले ही सार्वजनिक जीवन में शुद्धि का व्यापक अभियान छेड़ना नितांत आवश्यक हो गया है। निश्चय ही इस अभियान में वही समुदाय अगुवा बन सका है, जो आजादी के बाद फैली भ्रष्टाचार की अमर बेलि से किसी तरह बच सकता है। सब के सब तो नहीं, पर छात्रों और समाज के सबसे बड़े देबे–कुचले वर्गों का एक बड़ा हिस्सा अभी भ्रष्टाचार से अछूता है। इन दोनों के तालमेल से चलने वाला आन्दोलन ही अंततः मूलभूत सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों के व्यापक अभियान का रूप ले सकता है''।[24]

आपातकाल लगने के बाद 29 जून 1975 के अंक में आमुख कथा के रूप में मराठी पत्रकार गोविन्द तलवलकर ने 'मुकदमा, फैसला और अब' शीर्षक में लिखा– ''न्यायाधीश सिन्हा के फैसले ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह उजागर की है कि देश की सर्वोच्च सत्ता पर आरूढ़ व्यक्ति भी न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है.....इसमें शक नहीं कि न्यायाधीश सिन्हा के निर्णय से इंदिरा गांधी के नेतृत्व को नैतिक धक्का लगा है, इसके अनेक परिणाम सामने आएंगे''।[25] हालांकि सेंसरशिप के दौर में अन्य समाचार पत्रों के समान धर्मयुग को भी व्यवसायिक मजबूरियों के चलते तटस्थ रूख अख्तियार करना पड़ा, फिर भी धर्मयुग ने दूसरे सांकेतिक तरीकों से अपनी बात रखनी जारी रखा। तत्कालीन मुख्य उप–संपादक और बाद में संपादक बने गणेश मंत्री बताते हैं– ''आपातकाल की स्थिति लागू थी, अनेक पत्रकार इंदिरा गांधी के समर्थन में झंडे लेकर सेंसरशिप का समर्थन कर रहे थे। उन दिनों मैंने भारती जी की अनुमति से धर्मयुग में 'गांधी और मैकियावैली' नामक लेख लिखा। वह लेख क्यों लिखा और उसमें क्या कहा गया है, इस बात को पाठक समझ गए। कई लोगों ने जेल से मुझे चिट्ठियां लिखीं और कहा कि तुमने अपनी बात कह दी। इसी तरह एक लेख में मैंने रूसी क्रान्ति के बाद अधिनायकवादी व्यवस्था की चर्चा करते हुए कहा – सिर्फ एक पार्टी के लिए अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता वस्तुतः अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तभी गुणकारी होती है जब वह सत्ता की निन्दा में की जा सके।'' 17 अप्रैल 1977 के अंक में आपातकाल और सेंसरशिप के दौरान की पत्रकारिता के विषय मे धर्मवीर भारती लिखते हैं– ''चूंकि उस समय आतंक के कारण, पाबंदियों के कारण चारों तरफ सन्नाटा था...हम जानते थे कि हमारे जैसे हजारों लेखक और पत्रकार हैं, जो चोट खाकर चुप बैठ गए हैं, उनके मन में गहरी घुटन है। विशेषतौर पर अपेक्षाकृत युवा पत्रकार जो इस घुटन को चुपचार सह रहे हैं, उसन सबको यह लगता है कि 'अब तो दादुर बोलिहै'। पावस के समय कोकिला का मौन हो जाना ही श्रेयस्कर है। जब आवाज पर लगी बेड़ियां कटेंगी तब अपने स्तर और मर्यादा में बोलेंगे– जो संवेदनशील पाठक थे, वे बिना कहे इस मौन का अर्थ समझ रहे थे..... ।''[26]

इस समय के एक अन्य प्रमुख साप्ताहिक समाचार पत्र 'दिनमान' की छवि समाजवादी विचारधारा के पोषक समाचार साप्ताहिक की रही। इसने लोहिया और उनके विचारों को काफी प्रमुखता से छापा, परन्तु उस दौर के एक अन्य बड़े समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण को दिनमान ने ज्यादा तरजीह नहीं दी, जबकि जे.पी. के नेतृत्व में गुजरात और बिहार में शुरू हुए छात्र आन्दोलनों ने देश के राजनीतिक इतिहास की दिशा बदल दी थी। दिनमान के संपादक रघुवीर सहाय थे, जिनकी छवि समाजवाद समर्थक, इंदिरा और कांग्रेस विरोधी थी, बावजूद इसके पत्र में जे.पी. आन्दोलन को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। हालांकि 16 जून 1974 को 'बिहार आन्दोलन का यथार्थ' शीर्षक से लिखे संपादकीय में आन्दोलन का समर्थन दिखता है– ''....फिर भी जिनके हाथ सत्ता है और जो जनता की नहीं, केवल हुकूमत की भाषा समझने के आदी हो चुके हैं, उनका मन इस आन्दोलन से इतना विचलित हो चुका है कि संदेह होता है कि वे इसे समझ पाएंगे या नहीं, वे इसे केवल कुर्सी हथियाने का मायाजाल कह रहे हैं''।[27] हां, जे.पी. आन्दोलन पर रिपोर्ट दिनमान में आपातकाल के बाद ही ज्यादा छपी हैं। दरअसल जब टाइम्स प्रबंधन को यह लगने लगा कि अब इंदिरा गांधी की सर्वशक्तिमान सत्ता वापस नहीं लौटने वाली है तो दिनमान का रवैया बदल गया। जयप्रकाश आन्दोलन के बारे में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। आपातकाल के बाद दिनमान ने 29 मई 1977 को सम्पूर्ण क्रान्ति पर एक बड़ी रपट छापी, साथ ही जयप्रकाश नारायण द्वारा छात्र युवा संघर्षवाहिनी को लिखे पत्र को 'ऐतिहासिक दस्तावेज' के रूप में प्रकाशित किया।[26] फरवरी 1978 के अंक से पत्र ने बनवारी की एक धारावाहिक रपट का प्रकाशन शुरू किया, जिसका शीर्षक था ''1974 में इसी समय''।

जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोपकर अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित कर दिया था और समाचार माध्यमों पर सेंसर लगा दिया तो वैचारिकता को पुष्ट करने वाले 'दिनमान' के पृष्ठों पर इसके खिलाफ कोई उत्तेजना नहीं दिखाई दी। इसके बरक्स इस दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तब सत्ता के संविधानेत्तर केन्द्र बन चुके संजय गांधी के बयानों और दौरों की खबरें दिनमान में प्रमुखता पा रही थीं। अनेक लोग मानते हैं कि आपातकाल में दिनमान की भूमिका निराशाजनक रही। उस दौर में दिनमान की संपादकीय टीम के वरिष्ठ सदस्य रहे महेश्वर दयाल गंगवार बताते हैं– ''जब इमरजेन्सी लगी तो मैंने पाया कि रघुवीर सहाय कसौटी पर खरे नहीं उतरे। जिस तरह वे कट्टर समाजवादी थे और कट्टर संपादक होने की उनकी छवि थी, पर उन्होंने घुटने टेक दिये। इंदिरा गांधी द्वारा बुलाई गई संपादकों की मीटिंग के बाद उन्होंने अपने स्टाफ मीटिंग में बाकायदा हिदायत दी थी कि 'अब हमें अपना रवैया बदलना होगा, हमें इमरजेन्सी

का विरोध तो करना ही नहीं है, बल्कि इसका समर्थन भी करना है'।'' यानि कि आपातकाल पर दिनमान की वैचारिकता कुद हो गई और उसके संघर्षी तेवर तिरोहित हो गए थे। जून, 1975 के बाद के अंकों में दिनमान ने प्रेस सेंसरशिप लगाने के औचित्य का प्रतिपादन करने वाले प्रधानमंत्री के बयानों को प्रमुखता से छापा।28 आपातकाल के दौरान दिनमान मे किस तरह की सामग्री छप रही थी इसकी झलक 20 जुलाई 1975 के अंक में छपी 'राहत की सांस' नामक सर्वेक्षण से मिल जाती है। यह सर्वेक्षण धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ– ''जब दिनमान संवाददाताओं से पिछले सप्ताह कहा गया कि वे अपने प्रदेश में आपात स्थिति के बाद दामों की गिरावट का हाल लिख भेजें तो उन्होंने खबर दी कि गृहणियां राहत की सांस लेने लगी हैं, दुकानदार और सरकारी कर्मचारी चौकन्ने हैं और कमाने वाले पुरूष खुश हैं।''[29] 1977 चुनावों की घोषणा के बाद भी रिपोर्टों और आलेखों के माध्यम से भी दिनमान ने काग्रेस व इंदिरा गांधी का प्रशस्ति गान जारी रखा और चुनावों में श्रीमती गांधी की भारी जीत की भविष्यवाणी की।[30]

तत्कालीन क्षेत्रीय समाचार पत्र–पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय पत्र–पत्रिकाओं का ही अनुसरण किया। हां, एकबात जो महत्वपूर्ण है वह यह कि क्षेत्रीय अखबारों में आपातकाल का असर काफी बाद में पड़ा और आपातकाल के बाद भी वे निष्पक्षता से खबरें छापते रहे। इस दौर में क्षेत्रीय समाचार पत्रों ने निरपेक्षता का भाव भी दिखाया। 'राजस्थान पत्रिका' के संपादक कुलिश ने एक साक्षात्कार में कहा– ''आपातकाल के बाद मैंने खुद अपनी आंखों से कुछ गोपनीय दस्तावेज देखे, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि 'राजस्थान पत्रिका' शुरू में स्वतन्त्र और निष्पक्ष अखबार था, परन्तु बाद के दिनों में 'होस्टाइल' हो गया है।'' वे कहते हैं कि उन्होंने कभी दबाव में होकर नहीं लिखा और जब आपातकाल लगा तो उन्होंने आन्दोलन से हटकर जनता की समस्याओं को सामने लाने की कोशिशें समाचारों द्वारा करना प्रारम्भ किया, इससे पत्रकारिता भी हुई और शासन का ध्यान नागरिक समस्याओं की ओर गया।[31] 'युगधर्म' द्वारा जे.पी. आन्दोलन का भरपूर समर्थन किया गया और इमरजेन्सी पर स्पेशल बुलेटिन निकाला गया। देश के प्रतिपक्ष के नेता मूर्धन्य अर्थशास्त्री एवं समाजवादी चिंतक मधु लिमये ने दो टूक बयान दिया कि आपातकाल लगाना इंदिरा जी की तानाशाही है और जनता को इसके विरूद्ध विद्रोह करना चाहिए। रायपुर संस्करण के संपादक बबन प्रसाद मिश्र ने एक कड़ा अग्रलेख लिखा, जिसका शीर्षक था 'डी.आई.आर. यानि डंडा इंदिरा रूल' और 'मीसा यानि मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा सॉवरेनिटी'। किन्तु बुलेटिन बंटते–बंटते ही युगधर्म की बिजली काट दी गई और युगधर्म के संपादक और पत्रकारों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए गए। मध्यप्रदेश में युगधर्म प्रेस पर ताला लग गया। मध्यप्रदेश से प्रकाशित होने वाले पत्र 'स्वदेश' ने जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन का समर्थन और आपातकाल का विरोध किया।[32] स्वदेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके संचालकों को जेल में डाल दिया गया, इनपर मीसा के तहत भी कार्यवाहियां हुईं। इसके विपरीत 'देशबन्धु' ने खुलकर इंदिरा गांधी और आपातकाल का समर्थन किया। उसने प्रेस सेंसरशिप पर एक लेख 'अनुशासन पर्व और लेखकों का कर्तव्य' प्रकाशित कर लेखकों को उनके कर्तव्य समझाए।[33] हालांकि बाद में आपातकाल की ज्यादतियों को देखकर पत्र ने आपातकाल और इंदिरा गांधी का विरोध भी करना शुरू किया और जब नए चुनावों की घोषणा हुई तो खुलकर आपातकाल और सेंसरशिप का विरोध प्रदर्शन भी किया।[34]

1948 को अपने प्रथम अंक में नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अन्तर्गत अमर उजाला लिखता है– '' 'अमर उजाला' राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र एवं समाजवाद के उन आदर्शों के लिए काम करेगा जो हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के तत्व रहे हैं।'' सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन के दौरान अमर उजाला ने आन्दोलन के समर्थन में अनेक समाचारों का प्रकाशन किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व तथा आन्दोलन के बढ़ते स्वरूप को लेकर खबरें छापी गईं, साथ ही साथ इंदिरा गांधी की सरकार को अपने निर्णयों की पुनः समीक्षा करने को कहा गया। 23 जून 1975 के संपादकीय का प्रमुख लेख था– ''यह राजनैतिक भंडई देश में आग फूंक देगी।'' 24 जून का संपादकीय था– ''जन सुरक्षा दांव पर'', यह लेख देश मे भड़क रही हिंसा पर लिखा गया था। एक अन्य लेख था– ''भारत एक बार फिर चौराहे पर''। 25 जून का लेख है– ''लोकतन्त्र दांव पर'', जिसके अन्त में कहा गया था कि 'जब न्यायपालिका में विचार चल रहा था तक संघर्ष का निमंत्रण सत्ताधारी दल की ओर से ही शुरू हुआ है।' इस दौर की अन्य खबरें जो अमर उजाला में प्रकाशित हुईं हैं– ''चन्द्रशेखर व साथियों द्वारा त्यागपत्र की मांग, विपक्षी नेताओं की घोषणा– त्यागपत्र न दिया तो देशव्यापी आन्दोलन, अब तो त्यागपत्र दे दें–शांतिभूषण, क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगी?, देश में आपातकाल की घोषणा, 27 जून से प्रकाशित खबरों में खबरों को सेंसर करने के प्रमाण मिलने लगते हैं। जैसे– आंतरिक उपद्रवों से भारत की सुरक्षा को खतरा, राष्ट्र की अखण्डता के लिए कठोर कार्रवाई करना जरूरी, इससे भी सशक्त कदम की जरूरत : प्रियरंजन दास मुंशी, 29 जून की खबरें हैं– समाचार पत्रों पर सेंसरशिप, आपात स्थिति का समर्थन, साहित्यकारों द्वारा आपातस्थिति का समर्थन आदि।35 जाहिर है सेंशरशिप का रंग अखबार पर चढ़ने लगा था।

3. निष्कर्ष–

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन के परिणाम हितकारी साबित हुए। भष्टाचार, कालेधन, जमाखोरी, तस्करी आदि पर तत्कालीन समय में कड़ाई से लगाम लगाई गई। बढ़ती महंगाई को रोकने में मदद मिली। लेकिन इन सबके लिए आपातकाल लगाना एक अहितकारी निर्णय रहा। लोकतन्त्रात्मक देश में आपातकाल का लगाया जाना उचित नहीं था। हालांकि संविधान में भी जरूरत पड़ने पर आपातकाल लगाने का जिक्र है लेकिन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में देश में लगाए गया आपातकाल गैर जरूरी और खुद को बचाए रखने का कदम ही मालूम होता है। इसके परिणाम घातक रहे। इसके क्रियान्वयन में भारी लापरवाही बरती गई और देश में तानाशाही का माहौल बन गया।

प्रेस पर थोपी गई सेंसरशिप से माहौल को सुधारने में कोई मदद नहीं मिली, उल्टे जनमानस में गलत संदेश गया। इस दौरान प्रेस की स्थिति और भूमिका पर नजर डालते हैं तो सरकार समर्थक पत्र–पत्रिकाओं के अलावा आपातकाल के पहले तक का मीडिया जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के साथ दिखाई पड़ता है। इस दौरान इन पत्र–पत्रिकाओं ने आन्दोलन और इसके प्रभावों के पक्ष में माहौल बनाने का कार्य किया। यह तत्कालीन पत्र–पत्रिकाओं का ही प्रभाव था कि साल भर के अन्दर ही यह जनान्दोलन दक्षिण के राज्यों (केरल के अलावा) को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में फैल चुका था। भ्रष्टाचार और कुशासन के विरूद्ध देश में विरोध का माहौल बनाने में पत्र–पत्रिकाओं की महती भूमिका

थी। हालांकि आपालकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप के चलते लगभग सभी समाचार पत्र–पत्रिकाएं वे चाहे सरकार समर्थक हों या विरोधी, सरकार के प्रति समर्पण की मुद्रा में थे। सभी इंदिरा गांधी और उनकी सरकार का प्रशस्ति गान कर रहे थे, और विपक्ष को संवैधानिक सीमा में रहने की सीख दे रहे थे। इस प्रशस्ति गान से जहां सरकार भ्रम की स्थिति में रही और उसे शासन के भयावह रूप और देश की स्थिति का सही ज्ञान नहीं हो सका, वहीं देश का नागरिक निराशा की स्थिति में रहा। उसका शोषण होता रहा, लेकिन उसकी आवाज को सामने लाने वाले पत्र–पत्रिकाएं कोमा में थे। आपातकाल हटते ही इसके त्वरित और क्रान्तिकारी परिणाम हुए और 1977 में हुए लोकसभा चुनावों इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली काग्रेस की भारी हार हुई और जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ।

आपातकाल में मीडिया की स्थिति के विषय में वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी का कथन महत्वपूर्ण है कि– ''पच्चीस साल पहले छब्बीस जून की सुबह इंडियन एक्सप्रेस के अपने केबिन में बैठे हुए मुझे लगा कि एक अंधेरी सुरंग में खड़ा हूं और आंखें खोले रखूं या बंद कर लूं, इससे अंधेरे के दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुरंग में चलता जाऊं तो कहां जाकर निकलूंगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। कहीं निकलूंगा भी या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं था। सुरंग है, अंधेरा है और जब तक सामने से कुछ दिखता नहीं तब तक यहीं ठिठके खड़े रहना है। खड़े रहो। साथी पत्रकार भी शायद अपनी अपनी अंधेरी सुरंग में खड़े थे और कहीं कुछ दिखे या हो तो हरकत में आएं, इसकी प्रतीक्षा में थे।[36]

सन्दर्भ–

1.जेपी : एक जीवनी, भ्रष्ट शासनतन्त्र, अजित भट्टाचार्य, वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर, वर्ष 2009, पृष्ठ–156।
2.आजादी के बाद का भारत, विपिन चन्द्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृष्ठ–329
3.एमजेन्सी इन पर्सपेक्टिव : रिप्रीव एण्ड चैलेंज, सच्चिदानन्द सिन्हा, लोकप्रकाशन, पटना, पृष्ठ–32
4.आजादी के बाद का भारत, विपिन चन्द्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृष्ठ–331
5.एवरीमैन्स, जुलाई 1973 अंक
6.रैडिकल ह्यूमनिष्ट, अगस्त 1972 अंक
7.जेपी : एक जीवनी, भ्रष्ट शासनतन्त्र, अमित भट्टाचार्य, वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर, पृष्ठ 160
8.स्टेट्समैन, 10 अप्रैल 1974 में उद्धृत, फैंसिन आर. फ्रैंकेल, इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी 1947–77, दिल्ली, 1978, पृष्ठ–518 में उल्लिखित
9.आपातकाल– हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता, अमरेन्द्र कुमार शर्मा, साहित्य भंडार प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 2011, पृष्ठ–32
10.मोरारजी देसाई से ओरियान फलासी की बातचीत, न्यू रिपब्लिक, फैंसिन आर. फ्रैंकेल, इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी 1947–77, दिल्ली, 1978, पृष्ठ–544 में उल्लिखित
11.आजादी के बाद का भारत, विपिन चन्द्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृष्ठ–339
12.आजादी के बाद का भारत, विपिन चन्द्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृष्ठ–340
13.इंदर मल्होत्रा, इंदिरा गांधी, लंदन, 1989, पृष्ठ–173, 182
14.आजादी के बाद का भारत, विपिन चन्द्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृष्ठ–344
15.मीडिया के सामाजिक सरोकार, भूमिका, कालूराम परिहार, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ–21
16.मीडिया के सामाजिक सरोकार, भूमिका, कालूराम परिहार, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ–11
17.हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं–3, अच्युतानन्द मिश्र, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–180
18.अग्रलेख, आज समाचार पत्र, सौर 11 असाढ़ 1984
19.हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं–2, अच्युतानन्द मिश्र, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–63
20.हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं–2, अच्युतानन्द मिश्र, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–122
21.हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं–2, अच्युतानन्द मिश्र, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–123
22.हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं–2, अच्युतानन्द मिश्र, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–243
23.दूसरी आजादी, रामकुमार भ्रमर, हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ–63
24.धर्मयुग, 17मार्च 1974, पृष्ठ–30
25.धर्मयुग, 29 जून 1975, पृष्ठ–1–2
26.हिन्दी पत्रकारिता के डेढ़ सौ वर्ष, धर्मवीर भारती
27.हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं–1, अच्युतानन्द मिश्र, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–235
28.दिनमान, 4 जनवरी 1976
29.दिनमान, 20 जुलाई 1975
30.दिनमान, 13 मार्च 1977
31.हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं–4, अच्युतानन्द मिश्र, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–26
32.हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं–4, अच्युतानन्द मिश्र, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–205

33.देशबन्धु, 27 जून 1975, 18 सितम्बर 1975
34.देशबन्धु, 29 जनवरी 1977
35.हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं–3, अच्युतानन्द मिश्र, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–294–297
36.प्रभाष जोशी, जब तोप मुकाबिल हो, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 96

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net